



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2014/माघ 11, 1935

No. 37]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2014/MAGHA 11, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 31 जनवरी, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता)

(संशोधन) विनियम, 2014

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/43/207.-बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 में—

(1) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,—

- (i) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्, —
 "(छक) "शुद्ध-मालियत" (या "शुद्ध मूल्य") का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (57) में इसके लिए नियत है ;";
 - (ii) खंड (ज) में, शब्द "प्रोस्पेक्टस (विवरण पत्रिका)", शब्दों " प्रोस्पेक्टस (विवरण पत्रिका) या शेल्फ प्रोस्पेक्टस" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे;
 - (iii) खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्, —
 "(ठक) "शेल्फ प्रोस्पेक्टस" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 31 में इसके लिए नियत है ; " ।
- (2) विनियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्, —

"शेल्फ प्रोस्पेक्टस दाखिल करना

6क. (1) विनियम 6 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित कंपनियाँ या एंटीटियाँ अपनी ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 31 के अधीन शेल्फ प्रोस्पेक्टस दाखिल कर सकेंगी, —

- क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (72) के अधीन यथा परिभाषित लोक वित्तीय संस्थाएँ, और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ड) के अधीन यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक; या
- ख. कर मुक्त प्रतिभूत बाँण्डों का सार्वजनिक निर्गम लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत निर्गमकर्ता, ऐसे कर मुक्त बाँण्ड निर्गमन की बाबत; या
- ग. अवसंरचना ऋण निधियाँ - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंककारी (गैर-बैंकिंग) वित्तीय कंपनियाँ; या
- घ. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंककारी (गैर-बैंकिंग) वित्तीय कंपनियाँ और राष्ट्रीय आवास बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत आवास वित्त कंपनियाँ, जो निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करती हों :
 - i. जिनकी शुद्ध-मालियत, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार, कम से कम 500 करोड़ रुपये की हो;
 - ii. जिनका अंतिम तीन वर्षों से वितरण योग्य लाभ का निरंतर पिछला (ट्रैक) रिकॉर्ड हो;
 - iii. शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अधीन निर्गमित प्रतिभूतियों को बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) द्वारा "एए-" के प्रवर्ग या इसके समतुल्य से कम की रेटिंग नियत न की गयी हो;
 - iv. कोई भी विनियामक कार्रवाई कंपनी या इसके संप्रवर्तकों या निदेशकों के खिलाफ बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक के समक्ष लंबित नहीं है;

- v. निर्गमकर्ता ने, अंतिम तीन वित्तीय वर्षों में, जमाओं या उन पर देय ब्याज के प्रतिसंदाय अथवा डिबेंचरों या अधिमानी शेयरों के मोचन अथवा किसी शेयरधारक को लाभांश के संदाय (भुगतान), अथवा किसी लोक वित्तीय संस्था या बैंककारी (बैंकिंग) कंपनी को किसी सावधि ऋण या उस पर देय ब्याज के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम न किया हो (चूक न की हो)।

या

ड. निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करने वाली सूचीबद्ध एंटिटियाँ :

- i. जिनके सार्वजनिक निर्गमित इक्विटी शेयर या ऋण प्रतिभूतियाँ निर्गम के ठीक पहले की कम से कम तीन वर्षों की अवधि से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं तथा जो निर्गमकर्ता और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ निर्गमकर्ता की उक्त प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं, के बीच किये गये सूचीबद्धता करार का अनुपालन करती रही हैं;
- ii. जिनकी शुद्ध-मालियत, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार, कम से कम 500 करोड़ रुपये की हो;
- iii. जिनका अंतिम तीन वर्षों से वितरण योग्य लाभ का निरंतर पिछला (ट्रैक) रिकॉर्ड हो;
- iv. शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अधीन निर्गमित प्रतिभूतियों को बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) द्वारा "एए-" के प्रवर्ग या इसके समतुल्य से कम की रेटिंग नियत न की गयी हो;
- v. कोई भी विनियामक कार्रवाई कंपनी या इसके संप्रवर्तकों या निदेशकों के खिलाफ बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक के समक्ष लंबित नहीं है ;
- vi. निर्गमकर्ता ने, अंतिम तीन वित्तीय वर्षों में, जमाओं या उन पर देय ब्याज के प्रतिसंदाय अथवा डिबेंचरों या अधिमानी शेयरों के मोचन अथवा किसी शेयरधारक को लाभांश के संदाय (भुगतान), अथवा किसी लोक वित्तीय संस्था या बैंककारी (बैंकिंग) कंपनी को किसी सावधि ऋण या उस पर देय ब्याज के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम न किया हो (चूक न की हो)।

(2) शेल्फ प्रोस्पेक्टस दाखिल करने वाला निर्गमकर्ता मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों और बोर्ड के पास सूचना ज्ञापन की प्रति दाखिल करेगा, रजिस्ट्रार के पास उसे दाखिल करते ही।

(3) सूचना ज्ञापन में कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013, जो भी लागू हो, तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अंतर्विष्ट होंगे और जिनमें संक्षिप्त निबंधन-पत्रक, तात्त्विक अद्यतनीकरणों (अपडेशन) जिनके अंतर्गत रेटिंग के तर्काधार के साथ रेटिंगों में संशोधन, यदि कोई हो, है और अनुसूची I में विनिर्दिष्ट वित्तीय अनुपातों, निर्गम से पूर्व और निर्गम के पश्चात् का परिवर्तन दर्शाते हुए, से संबंधित प्रकटीकरण सम्मिलित होंगे।

(4) चार से अधिक निर्गम एकल शेल्फ प्रोस्पेक्टस के माध्यम से नहीं लाये जायेंगे । "

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III /4/असा./69 जैड बी/2013]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008, मूल विनियम, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/13/127878 द्वारा, 6 जून 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. ये विनियम तत्पश्चात् 12 अक्तूबर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/19/5392, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st January, 2014

Securities And Exchange Board of India (Issue And Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2014

No. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2014.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 -

(1) in regulation 2, in sub-regulation (1),—

(i) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely,—

“(ga) “net worth” shall have the same meaning as assigned to it in clause (57) of section 2 of the Companies Act, 2013;”;

(ii) in clause (j), the word “prospectus”, shall be substituted with the words “a prospectus or a shelf prospectus”;

(iii) after clause (l), the following clause shall be inserted, namely,—

“(la) “shelf prospectus” shall have the same meaning as assigned to it in section 31 of the Companies Act, 2013;”.

(2) after regulation 6, following regulation shall be inserted, namely,-

"Filing of Shelf Prospectus.

6A. (1) Without prejudice to the regulation 6, following companies or entities may file shelf prospectus under section 31 of Companies Act, 2013 for public issuance of their debt securities,-

- a. Public financial institutions as defined under clause (72) of section 2 of the Companies Act, 2013, and scheduled banks as defined under clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934; or
- b. Issuers authorized by the notification of Central Board of Direct Taxes to make public issue of tax free secured bonds, with respect to such tax free bond issuances; or
- c. Infrastructure Debt Funds – Non-Banking Financial Companies regulated by Reserve Bank of India; or
- d. Non-Banking Financial Companies registered with Reserve Bank of India and Housing Finance Companies registered with National Housing Bank complying with the following criteria:
 - i. having a net worth of at-least Rs.500 crore, as per the audited balance sheet of the preceding financial year;
 - ii. having consistent track record of distributable profit for the last three years;
 - iii. securities issued under the shelf prospectus have been assigned a rating of not less than "AA-" category or equivalent by a credit rating agency registered with the Board;
 - iv. no regulatory action is pending against the company or its promoters or directors before the Board, Reserve Bank of India or National Housing Bank;
 - v. the issuer has not defaulted in the repayment of deposits or interest payable thereon, redemption of debentures or preference shares or payment of dividend to any shareholder, or repayment of any term loan or interest payable thereon to any public financial institution or banking company, in the last three financial years.

or
- e. Listed entities complying with the following criteria:
 - i. whose public issued equity shares or debt securities are listed on recognized stock exchange for a period of at least three years immediately preceding the issue and have been complying with the listing agreement entered into between the issuer and the recognized stock exchanges where the said securities of the issuer are listed;
 - ii. having a net worth of at-least Rs.500 crore, as per the audited balance sheet of the preceding financial year;
 - iii. having consistent track record of distributable profit for the last three years;
 - iv. securities issued under the shelf prospectus have been assigned a rating of not less than "AA-" category or equivalent by a credit rating agency registered with the Board;

- v. no regulatory action is pending against the company or its promoters or directors before the Board, Reserve Bank of India or National Housing Bank;
- vi. the issuer has not defaulted in the repayment of deposits or interest payable thereon, redemption of debentures or preference shares or payment of dividend to any shareholder, or repayment of any term loan or interest payable thereon to any public financial institution or banking company, in the last three financial years.

(2) The issuer filing a shelf prospectus shall file a copy of an information memorandum with the recognised stock exchanges and the Board, immediately on filing the same with the Registrar.

(3) The information memorandum shall contain the disclosures specified in Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013, whichever is applicable and rules made thereunder and shall include disclosures regarding summary term sheet, material updations including revision in ratings, if any along with the rating rationale and financial ratios specified in Schedule I, indicating the pre and post issue change.

(4) Not more than four issuances shall be made through a single shelf prospectus.”

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT./III/4/Exty./69 ZB/2013]

Footnotes :

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, the principal regulations were published in the Gazette of India on 6th June, 2008 vide No. LAD-NRO/GN/2008/13/127878.
2. These regulations were subsequently amended on October 12th, 2012 by SEBI (Issue and Listing of Debt Securities)(Amendment)Regulations, 2012 vide LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392.